सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2025/57 दर्ज तिथिः–10.02.2025

1. रिड़मलराम पुत्र सोनाराम
   जाति विश्नोई निवासी कांधी की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
   बजरिये वादमित्र
   हरीराम पुत्र रिड़मलराम
   जाति विश्नोई निवासी कांधी की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

.................वादी

बनाम

1. हनुमानराम पुत्र जीयाराम
2. केलीदेवी पत्नी श्रवणकुमार
3. शांति पत्नी भागीरथ
4. मोहनी पत्नी ओमप्रकाश
   जाति विश्नोई निवासी कांधी की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

..................असल प्रतिवादीगण

5. तहसीलदार एवं उपपंजीयक गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

.............तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः–श्री रामजीवन विश्नोई
अप्रार्थीः–श्री मोहनलाल विश्नोई

प्रार्थना पत्रः– आदेश–07 नियम–11
सिविल प्रक्रिया संहिता–1908

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–22.12.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना–पत्र सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के अन्तर्गत बाबत् निर्णय प्रस्तुत हुई। प्रकरण का सुक्ष्म एवं सारतः वृतान्त इस प्रकार है कि
   - मुतनाजा आराजी हाल खसरा संख्या 1577 एवं 1577/1 मौजा कांधी की ढाणी तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित है। उक्त आराजी का मूल खसरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.24 19:05:53 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 1577 मौजा गुड़ामालानी था। उक्त आराजी का मूल खातेदार विजयसिंह पुत्र सरदारसिंह कौम राजपुत निवासी गुड़ामालानी के नाम दर्ज रिकॉर्ड था।

- कि दिनांक 25.07.1968 को उक्त आराजी का मूल खातेदार विजयसिंह पुत्र सरदारसिंह कौम राजपुत निवासी गुड़ामालानी ने उक्त आराजी वादी रिड़मल पुत्र सोना को जरिये पंजीबद्ध बयनामा अपना प्रतिफल प्राप्त करते हुए बेचान कर कब्जा सुपुर्द कर दिया। परंतु वादी के अनपढ़ होने के कारण उक्त बेचान का नामान्तरकरण दर्ज नहीं करवाया जा सका।
- कि उक्त आराजी का मूल खातेदार विजयसिंह पुत्र सरदारसिंह कौम राजपुत निवासी गुड़ामालानी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में बदस्तूर जारी रहा। सन 1970 में उक्त आराजी का मूल खातेदार विजयसिंह पुत्र सरदारसिंह कौम राजपुत निवासी गुड़ामालानी के फौतगी का नामान्तरकरण इन्द्रसिंह पुत्र विजयसिंह के नाम दर्ज किया गया।
- कि इन्द्रसिंह पुत्र विजयसिंह द्वारा दिनांक 29.01.2009 को उक्त आराजी का बेचान शांति पत्नी पुरखाराम, लक्ष्मी पत्नी जगाराम, तेजपाल पुत्र भागीरथराम व मानाराम पुत्र जीयाराम को कर दिया। तत्पश्चात खरीदकर्ताओं में से लक्ष्मी पत्नी जगाराम व तेजपाल पुत्र भागीरथराम द्वारा दिनांक 16.05.2016 को अग्रिम बेचान शांति पत्नी पुरखाराम को कर दिया। तत्पश्चात खरीदकर्ताओं में से शांति पत्नी पुरखाराम द्वारा दिनांक 03.03.2023 को अग्रिम बेचान केली पत्नी श्रवणकुमार को कर दिया।
- अतः उक्त आराजी पर बयनामा दिनांक 25.07.1968 के पश्चात समस्त बयनामा को निरस्त करते हुए वादी का उक्त सम्पत्ति में निहित हक अनुसार खातेदारी अधिकारों की घोषणा करते हुए प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष स्वीकार करने का निवेदन किया।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण असालतन–वकालतन उपस्थित न्यायालय हुए। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त प्रकरण में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रतिवादी का सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर दावा वादी खारिज किया जाने का निम्न प्रकार निवेदन किया–

    - कि रिड़मलराम वर्तमान में स्वयं जीवित है। जबकि हस्तगत दावा उनके पुत्र हरीराम द्वारा वादमित्र बनकर प्रस्तुत किया है। इस प्रकार बिना सक्षम न्यायालय से स्वयं को वादमित्र घोषित किये तथा सक्षम चिकित्सक द्वारा बिना चिकित्सकीय परीक्षण किये रिड़मलराम को विकृत चित, निर्योग्य व्यक्ति घोषित किये तथा रिड़मलराम को बिना बताए अपने आप ही वादमित्र बनकर गलत प्रक्रिया के अनुसार दावा प्रस्तुत किया है। अतः हस्तगत दावा बिना वादहेतुक के प्रस्तुत होने तथा विधि वर्जित होने के कारण हस्तगत दावा काबिल–ए–खारिज है।

3. प्रकरण में उभयपक्षकारान की उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी/प्रार्थी ने दौराने जिरह प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.24 19:05:53 IST
Reason: SelfAttested

हुये प्रतिवादी का सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—7 नियम—11 के अन्तर्गत प्रार्थना—पत्र स्वीकार किया जाकर दावा वादी खारिज किया जाने का निवेदन किया। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी / अप्रार्थी ने प्रार्थी / प्रतिवादी का सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—7 नियम—11 के अन्तर्गत प्रार्थना—पत्र खारिज फरमाया जाने का निम्न प्रकार निवेदन किया—

- कि वादी द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—32 नियम—15 के तहत वादमित्र नियुक्त किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हुआ है।
- कि वादी रिड़मलराम वृद्ध तथा विकृत चित, निर्योग्य व्यक्ति होने के कारण वादमित्र के जरिये ही दावा प्रस्तुत कर सकता है।
- कि प्रार्थी / प्रतिवादी का सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—7 नियम—11 के अन्तर्गत प्रार्थना—पत्र सारहीन होने तथा प्रावधान के अंतर्गत नहीं होने के कारण खारिज किये जाने का निवेदन किया।

4. प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया है। बाद पत्रावली अवलोकन व मनन बहस ज्ञात होता है कि प्रकरण सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—7 नियम—11 के प्रार्थना पत्र से संबंधित है। प्रकरण में तथ्यों के कानूनी बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण से पूर्व सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—7 नियम—11 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः—

> ***11. Rejection of plaint.-*** *The plaint shall be rejected in the following cases:—*
> *(a) where it does not disclose a cause of action;*
> *(b) where the relief claimed is undervalued, and the plaintiff, on being required by the court to correct the valuation within a time to be fixed by the court, fails to do so;*
> *(c) where the relief claimed is properly valued, but the plaint is written upon paper insufficiently stamped, and the plaintiff, on being required by the court to supply the requisite stamp paper within a time to be fixed by the Court, fails to do so;*
> *(d) where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law;*
> *(e) where it is not filed in duplicate;*
> *(f) where the plaintiff fails comply with the provision of Rule 9.*
>
> ***Provided that*** *the time fixed by the court for the correction of the valuation or supplying of the requisite stamp papers shall not be extended unless the court, for reasons to be recorded, is satisfied that the plaintiff was prevented by any cause of an exceptional nature from correcting the valuation or supplying the requisite stamp papers, as the case may be within the time fixed by the court and that refusal to extend such time would cause grave injustice to the plaintiff.*

5. इस संदर्भ में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा Smt. V. Bragan Nayagi vs R. R. Jeyaprakasam प्रकरण में दिनांक 01.04.2015 को दिये गये निर्णय के प्रासंगिक पैरा का उद्धरण प्रासंगिक है जो कि इस प्रकार हैः—

> While filing an application under Order 7 Rule 11 of the Code of Civil Procedure, the Court is bound to see whether the case on hand falls within six limbs stated in the said Rule. If the suit

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.24 19:05:53 IST
Reason: SelfAttested

is not falling under any of those categories, the plaint cannot be rejected.

6. सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 एवं माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा Smt.V.Bragan Nayagi vs R.R.Jeyaprakasam प्रकरण में दिनांक 01.04. 2015 को दिये गये निर्णय में बताये गये 06 आधारों के उक्त साधारण पठन से ज्ञात होता है कि किसी वाद पत्र को निम्न 06 आधारों पर खारीज किये जाने के प्रावधान बनाये गये हैं:–

1. वाद पत्र द्वारा वाद हेतुक का प्रकटीकरण नहीं किया जाना।
2. वाद पत्र में अनुतोष के मूल्य की वास्तविक्ता से कम गणना करना तथा निर्धारित समय के अवसर के तहत उक्त त्रुटिपूर्ण गणना को दुरूस्त नहीं करना।
3. वाद पत्र में अनुतोष के मूल्य की सटीक गणना करना परन्तु उसी अनुरूप उचित स्टाम्प वाद पत्र पर नहीं लगाना तथा निर्धारित समय के अवसर के तहत उक्त त्रुटिपूर्ण स्टाम्प की कमी को दुरूस्त नहीं करना।
4. वाद पत्र के अभिकथनों के आधार पर वाद–पत्र का विधि द्वारा वर्जित पाया जाना।
5. वाद पत्र का बहु प्रतिलिपियों में प्रस्तुत नहीं किया जाना।
6. वादी द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–9 के प्रावधानों की अनुपालना करने में विफल होना।

Object

7. सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के संपूर्ण विवेचन हेतु न्यायिक दृष्टान्तों का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। सर्वप्रथम सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के **उद्देश्य (Object)** के संबंध में न्यायिक दृष्टान्तों उद्धरण यहां प्रासंगिक है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 9519 / 2019 उनवान *Dahiben vs Arvindbhai Kalyanji Bhanusali* में दिनांक 09.07. 2020 को सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के उद्देश्य (Object) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:–

The underlying object of Order VII Rule 11 (a) is that if in a suit, no cause of action is disclosed, or the suit is barred by limitation under Rule 11 (d), the Court would not permit the plaintiff to unnecessarily protract the proceedings in the suit. In such a case, it would be necessary to put an end to the sham litigation, so that further judicial time is not wasted.

8. इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्वाचन याचिका उनवान Azhar Hussain vs Rajiv Gandhi में दिनांक 25.04.1986 को सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के उद्देश्य (Object) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:–

The whole purpose of conferment of such powers is to ensure that a litigation which is meaningless and bound to prove abortive should not be permitted to occupy the time of the court and exercise the mind of the respondent. The sword of Damocle need not be kept hanging over his head unnecessarily without

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.24 19:05:53 IST
Reason: SelfAttested

point or purpose. Even in an ordinary Civil litigation the Court readily exercises the power to reject a plaint if it does not disclose any cause of action. Or the power to direct the concerned party to strike out unnecessary, scandalous, frivolous or vexatious parts of the pleadings. Or such pleadings which are likely to cause embarrassment or delay the fair trial of the action or which is otherwise an abuse of the process of law. An order directing a party to strike out a part of the pleading would result in the termination of the case arising in the context of the said pleading. The Courts in exercise of the powers under the Code of Civil Procedure can also treat any point going to the root of the matter such as one pertaining to jurisdiction or maintainability as a preliminary point and can dismiss a suit without proceeding to record evidence and hear elaborate arguments in the context of such evidence, if the Court is satisfied that the action would terminate in view of the merits of the preliminary point of objection.

9. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 448/2004 उनवान *Sopan Sukhdeo Sable & Ors vs Assistant Charity Commissioner* में दिनांक 23.01.2004 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के उद्देश्य (Object) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार हैः–

The real object of Order VII Rule 11 of the Code is to <u>keep out of courts irresponsible law suits.</u> Therefore, the Order X of the Code is a tool in the hands of the Courts by resorting to which and by searching examination of the party in case the Court is prima facie of the view that the suit is an abuse of the process of the court in the sense that it is a bogus and irresponsible litigation, the jurisdiction under Order VII Rule 11 of the Code can be exercised.

<u>Role of the Court/Judge</u>

10. इसी प्रकार सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के तहत न्यायालय/न्यायाधीश की भूमिका (Role of the court/judge) के संबंध में न्यायिक दृष्टान्तों उद्धरण यहां प्रासंगिक है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उनवान T. Arivandandam vs T. V. Satyapal & Another में दिनांक 14.10.1977 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के तहत न्यायालय/न्यायाधीश की भूमिका (Role of the court/judge) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार हैः–

The learned Munsif must remember that if on a meaningful-not formal-reading of the plaint it is manifestly vexatious, and meritless, in the sense of not disclosing a clear right to sue, be should exercise his power under Or. VII r. 1 1 C.P.C. taking care to see that the ground mentioned therein is fulfilled. And, if clever, drafting has created the illusion of a cause of action, nip it in the bud at the first hearing by examining the party searchingly under Order X C.P.C. <u>An activist Judge is the answer to irresponsible law suits.</u> The trial court should insist imperatively on examining the party at the first bearing so that bogus litigation can be shot down at the earliest stage. The Penal Code (Ch. XI) is also resourceful enough to meet such men, and must be triggered against them. In this case, the learned Judge to his cost realised what George Bernard Shaw

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.24 19:05:53 IST
Reason: SelfAttested

> *remarked on the assassination of Mahatma Gandhi "It is dangerous to be too good."*

11. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 448/2004 उनवान Sopan Sukhdeo Sable & Ors vs Assistant Charity Commissioner में दिनांक 23.01.2004 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—7 नियम—11 के तहत न्यायालय/न्यायाधीश की भूमिका (Role of the court/judge) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार हैः—

> *The trial Court must remember that if on a meaningful and not formal reading of the plaint it is manifestly vexatious and meritless in the sense of not disclosing a clear right to sue, it should exercise the power under Order VII Rule 11 of the Code taking care to see that the ground mentioned therein is fulfilled. If clever drafting has created the illusion of a cause of action, it has to be nipped in the bud at the first hearing by examining the party searchingly under Order X of the Code.*

Material to be considered

12. इसी प्रकार सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—7 नियम—11 के तहत वाद पत्र के अभिकथनों के पठन (Material to be considered) के संबंध में न्यायिक दृष्टान्तों उद्धरण यहां प्रासंगिक है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 9519/2019 उनवान *Dahiben vs Arvindbhai Kalyanji Bhanusali* में दिनांक 09.07.2020 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—7 नियम—11 के तहत वाद पत्र के अभिकथनों के पठन (Material to be considered) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार हैः—

> *At this stage, the pleas taken by the defendant in the written statement and application for rejection of the plaint on the merits, would be irrelevant, and cannot be adverted to, or taken into consideration. The test for exercising the power under Order VII Rule 11 is that if the averments made in the plaint are taken in entirety, in conjunction with the documents relied upon, would the same result in a decree being passed.*

Test

13. इसी प्रकार सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—7 नियम—11 के तहत वाद पत्र के परीक्षण (Test) के संबंध में न्यायिक दृष्टान्तों उद्धरण यहां प्रासंगिक है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 9519/2019 उनवान *Dahiben vs Arvindbhai Kalyanji Bhanusali* में दिनांक 09.07.2020 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—7 नियम—11 के तहत वाद पत्र के परीक्षण (Test) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार हैः—

> *At this stage, the pleas taken by the defendant in the written statement and application for rejection of the plaint on the merits, would be irrelevant, and cannot be adverted to, or taken into consideration. The test for exercising the power under Order VII Rule 11 is that if the averments made in the plaint are taken in entirety, in conjunction with the documents relied upon, would the same result in a decree being passed.*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.24 19:05:53 IST
Reason: SelfAttested

> *Whether a plaint discloses a cause of action or not is essentially a question of fact. But whether it does or does not must be found out from reading the plaint itself. For the said purpose, the averments made in the plaint in their entirety must be held to be correct. The test is as to whether if the averments made in the plaint are taken to be correct in their entirety, a decree would be passed." In Hardesh Ores (P.) Ltd. v. Hede & Co.5 the Court further held that it is not permissible to cull out a sentence or a passage, and to read it in isolation. It is the substance, and not merely the form, which has to be looked into. The plaint has to be construed as it stands, without addition or subtraction of words.*

How to read and examine the plaint

14. इसी प्रकार सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—7 नियम—11 के तहत वाद पत्र के पठन एवं परीक्षण (How to read and examine the plaint) के संबंध में न्यायिक दृष्टान्तों उद्धरण यहां प्रासंगिक है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 9519/2019 उनवान *Dahiben vs Arvindbhai Kalyanji Bhanusali* में दिनांक 09.07.2020 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—7 नियम—11 के वाद पत्र के पठन एवं परीक्षण (How to read and examine the plaint) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार हैः—

> *If on a meaningful reading of the plaint, it is found that the suit is manifestly vexatious and without any merit, and does not disclose a right to sue, the court would be justified in exercising the power under Order VII Rule 11 CPC. 12.9 The power under Order VII Rule 11 CPC may be exercised by the Court at any stage of the suit, either before registering the plaint, or after issuing summons to the defendant, or before conclusion of the trial, as held by this Court in the judgment of Saleem Bhai v. State of Maharashtra.*
>
> *A three-Judge Bench of this Court in State of Punjab v. Gurdev Singh,13 held that the Court must examine the plaint and determine when the right to sue first accrued to the plaintiff, and whether on the assumed facts, the plaint is within time. The words "right to sue" means the right to seek relief by means of legal proceedings. The right to sue accrues only when the cause of action arises. The suit must be instituted when the right asserted in the suit is infringed, or when there is a clear and unequivocal threat to infringe such right by the defendant against whom the suit is instituted.*

15. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 448/2004 उनवान Sopan Sukhdeo Sable & Ors vs Assistant Charity Commissioner में दिनांक 23.01. 2004 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—7 नियम—11 के तहत वाद पत्र के पठन एवं परीक्षण (How to read and examine the plaint) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार हैः—

> *There cannot be any compartmentalization, dissection, segregation and inversions of the language of various paragraphs in the plaint. If such a course is adopted it would run counter to the cardinal canon of interpretation according to*

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.24 19:05:53 IST
Reason: SelfAttested

which a pleading has to be read as a whole to ascertain its true import. It is not permissible to cull out a sentence or a passage and to read it out of the context in isolation. Although it is the substance and not merely the form that has to be looked into, the pleading has to be construed as it stands without addition or subtraction or words or change of its apparent grammatical sense. The intention of the party concerned is to be gathered primarily from the tenor and terms of his pleadings taken as a whole. At the same time it should be borne in mind that no pedantic approach should be adopted to defeat justice on hair-splitting technicalities.

Essence

16. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील 330 / 2010 उनवान *Ram Kripal Das Ji Charitable Trust vs Phool Chand* में दिनांक 29.02.2012 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—7 नियम—11 के *सारांश* (Essence) को स्पष्ट किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार हैः—

11. Before dealing with the factual scenario, the spectrum of Order 7 Rule 11 in the legal ambit needs to be noted. The legal position in regard to Order 7 Rule 11 CPC may be summerised as below:

(i) The relevant facts which need to be looked into for deciding an application under Order 7 Rule 11 are the averments made in the plaint. The trial Court can exercise the power at any stage of the suit-before registering the plaint or after issuing summons to the defendant at any time before the conclusion of the trial. For the purposes of deciding an application under clauses (a) and (d) of Order 7 Rule 11 of the Code, the averments in the plaint are germane; the pleas taken by the defendant in the written statement would be wholly irrelevant at that stage.

(ii) The basic question to be decided while dealing with an application filed under Order 7 Rule 11 of the Code is whether a real cause of action has been set out in the plaint or something purely illusory has been stated with a view to get out of Order 7 Rule 11 of the Code.

(iii) The Court must remember that if on a meaningful and not formal reading of the plaint it is manifestly vexatious and meritless in the sense of not disclosing a clear right to sue, it should exercise the power under Order 7 Rule 11 of the Code taking care to see that the ground mentioned therein is fulfilled. If clever drafting has created the illusion of a cause of action, it has to be nipped in the bud at the first hearing by examining the party searchingly under Order 10 of the Code.

(iv) For deciding such an application not any particular plea has to be considered, and the whole plaint has to be read. Only a part of the plaint cannot be rejected and if no cause of action is disclosed, the plaint as a whole must be rejected.

(v) Rule 11 of Order 7 CPC lays down an independent remedy made available to the defendant to challenge the maintainability of the suit itself, irrespective of his right to contest the same on merits. The law ostensibly does not contemplate at any stage when the objections can be raised, and also does not say in express terms about the filing of the written statement. Instead, the word "shall" is used, clearly implying thereby that it casts a duty on the court to perform its obligations in rejecting the plaint when the same is hit by any of

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.24 19:05:53 IST
Reason: SelfAttested

> *the infirmities provided in the various clauses of Rule 11, even without intervention of the defendant. Even if no objection is taken by the defendant by filing an application under this provision, the court itself is empowered to reject the plaint if it finds that the case is covered within the four corners of this provision.*
>
> *(vi) It is well settled that the question of jurisdiction namely whether a suit is exclusively triable by a revenue court or a Civil Court can take cognizance of it has to be decided on the allegations made in the plaint. It is also further settled that it is the substance of the plaint and the true nature of the suit that is to be seen to determine the question of jurisdiction. If in substance the relief claimed is one which the revenue court alone is entitled to give, the jurisdiction of the civil court will be ousted even though it may require the revenue court to incidentally determine some ancillary facts. In order to determine the true nature of the relief claimed in a suit, the pith and substance and not the form in which the relief may be couched has to be considered. Each case has to be examined on its own particular facts and no universal rule can be applicable to every case.*

17. उपरोक्त विधिक प्रावधान न्यायिक दृष्टांतों के परिपेक्ष्य में प्रकरण का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। सर्वप्रथम प्रकरण में वादी के दिनांक 25.01.2017 को अपने हक को सुजाराम के पक्ष में हकतर्क करते हुए हकतर्कनामा पंजीबद्ध करवाने के पश्चात् वादी को उक्त दावा प्रस्तुत करने का वादहेतुक उत्पन्न नहीं होने के आधार पर सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के उपबन्ध–ए के तहत वाद कारण उत्पन्न नहीं होने के आधार पर दावा खारिज करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। वादी द्वारा इस संबंध में अभिकथन किया गया है कि वादी द्वारा केवल घोषणा का दावा प्रस्तुत किये जाने तथा हाजा न्यायालय में घोषणा का दावा को वादी द्वारा उक्त दावा प्रस्तुत करने का वादहेतुक उत्पन्न होने के आधार पर वादी का दावा चलने योग्य है।

18. सर्वप्रथम प्रकरण में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के उपबन्ध–अ के तहत वाद हेतुक के प्रकटीकरण (Cause of action) के संबंध में न्यायिक दृष्टान्तों उद्धरण यहां प्रासंगिक है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 9159 / 2003 उनवान *M/S. Kusum Ingots & Alloys Ltd vs Union Of India And Anr* में दिनांक 28.04.2004 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के उपबन्ध–अ के तहत वाद हेतुक के प्रकटीकरण (Cause of action) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार हैः–

> *Cause of Action:*
>
> *Cause of action implies a right to sue. The material facts which are imperative for the suitor to allege and prove constitutes the cause of action. Cause of action is not defined in any statute. <u>It has, however, been judicially interpreted inter alia to mean that every fact which would be necessary for the plaintiff to prove, if traversed, in order to support his right to the judgment of the Court. Negatively put, it would mean that everything which, if not proved, gives the defendant an immediate right to judgment, would be part of cause of action.</u> Its importance is beyond any doubt. <u>For every action, there has to be a cause of action, if not,</u>*

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.24 19:05:53 IST
Reason: SelfAttested

> *the plaint or the writ petition, as the case may be, shall be rejected summarily.*

19. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 9159/2003 उनवान *Swamy Atmananda & Ors vs Sri Ramakrishna Tapovanam & Ors* में दिनांक 13.04.2005 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—7 नियम—11 के उपबन्ध—अ के तहत वाद हेतुक के प्रकटीकरण (Cause of action) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार हैः—

> *In Stroud's Judicial Dictionary a cause of action is stated to be the entire set of facts that give rise to an enforceable claim; the phrase comprises every fact which, if traversed, the plaintiff must prove in order to obtain judgment.*
>
> *A cause of action, thus, means every fact, which, if traversed, it would be necessary for the plaintiff to prove in order to support his right to a judgment of the Court. In other words, it is a bundle of facts which taken with the law applicable to them gives the plaintiff a right to relief against the defendant. It must include some act done by the defendant since in the absence of such an act no cause of action can possibly accrue. It is not limited to the actual infringement of the right sued on but includes all the material facts on which it is founded.*

20. माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा उनवान *M/S. Narasu'S Coffee Company vs R. P. Sarathy* में दिनांक 17.04.2014 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—7 नियम—11 के उपबन्ध—अ के तहत वाद हेतुक के प्रकटीकरण (Cause of action) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार हैः—

> It is a settled proposition of law that to reject the plaint under Order 7 Rule 11 (a) of the Code, the petitioner / defendant should establish that there is no legally sustainable cause of action, to seek the relief as prayed for in the plaint. Similarly, as per Rule 11 (d) of Order 7 of the Code, if the suit is barred by any statute or if it is an abuse of process of Court, it could be ordered. In order to establish that there is no cause of action and seek an order to reject the plaint, the defendant is not entitled to rely on his written statement. The applicant / defendant has to establish the fact that there is no cause of action, only based on the averments of the plaint and the admission made by the plaintiff, on the factual aspect.

21. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 448/2004 उनवान Sopan Sukhdeo Sable & Ors vs Assistant Charity Commissioner में दिनांक 23.01.2004 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—7 नियम—11 के उपबन्ध—अ के तहत वाद हेतुक के प्रकटीकरण (Cause of action) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार हैः—

> *The trial Court must remember that if on a meaningful and not formal reading of the plaint it is manifestly vexatious and meritless in the sense of not disclosing a clear right to sue, it should exercise the power under Order VII Rule 11 of the Code taking care to see that the ground mentioned therein is fulfilled. If clever drafting has created the illusion of a cause of action, it has to be nipped in the bud at the first hearing by examining the party searchingly under Order X of the Code.*

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.24 19:05:53 IST
Reason: SelfAttested

The plea clearly overlooks the basic distinction between statements of the facts disclosing cause of action and the reliefs sought for. The reliefs claimed do not constitute the cause of action. On the contrary, they constitute the entitlement, if any, on the basis of pleaded facts. As indicated above, Order VI Rule 2 requires that pleadings shall contain and contain only a statement in a concise form of the material facts on which the party pleading relies for his claim. If the plea of Mr. Savant, learned counsel for the respondent-trust is accepted the distinction between the statement of material facts and the reliance on them for the claim shall be obliterated. What is required in law is not the piecemeal reading of the plaint but in its entirety. Whether the reliefs would be granted on the pleaded facts and the evidence adduced is totally different from the relief claimed. All the reliefs claimed may not be allowed to a party on the pleadings and the evidence adduced. Whether part of the relief cannot be granted by the Civil Court is a different matter from saying that because of a combined claim of reliefs the jurisdiction is ousted or no cause of action is disclosed. Considering the reliefs claimed vis-a- vis the pleadings would not mean compartmentalization or segregation, in that sense.

22. माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा उनवान *Electronic Machine Tools Limited vs Power Engineers* में दिनांक 14.02.2011 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—7 नियम—11 के उपबन्ध—अ के तहत वाद हेतुक के प्रकटीकरण (Cause of action) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार हैः—

16. It is an admitted fact that the averments in the plaint are sufficient to prove that where the cause of action is mentioned and averred in the plaint, there is no need to decide as to whether the cause of action averred in the plaint is true and correct.

23. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 5665/2002 उनवान *Liverpool & London S.P. & I Asson. ... vs M.V. Sea Success I & Anr* में दिनांक 20.11.2003 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—7 नियम—11 के उपबन्ध—अ के तहत वाद हेतुक के प्रकटीकरण (Cause of action) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार हैः—

REJECTION OF PLAINT:

Whether a plaint discloses a cause of action or not is essentially a question of fact. But whether it does or does not must be found out from reading the plaint itself. For the said purpose the averments made in the plaint in their entirety must be held to be correct. The test is as to whether if the averments made in the plaint are taken to be correct in its entirety, a decree would be passed.

CAUSE OF ACTION:

A cause of action is a bundle of facts which are required to be pleaded and proved for the purpose of obtaining relief claimed

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.24 19:05:53 IST
Reason: SelfAttested

> *<u>in the suit. For the aforementioned purpose, the material facts are required to be stated but not the evidence except in certain cases where the pleading relies on any misrepresentation, fraud, breach of trust, wilful default, or undue influence.</u>*

24. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उनवान *I.T.C. Limited vs The Debts Recovery Appellate* में दिनांक 19.12.1997 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—7 नियम—11 के उपबन्ध—अ के तहत वाद हेतुक के प्रकटीकरण (Cause of action) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:—

> *Question is whether a real cause of action has been set out in the plaint or something purely illusory has been stated with a view to get out of Order 7 Rule 11 C.P.C. <u>Clever drafting creating illusions of cause of action are not permitted in law and a clear right to sue should be shown in the plaint.</u>*

25. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उनवान *Vijay Pratap Singh vs Dukh Haran Nath Singh And Another* में दिनांक 19.01.1962 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—7 नियम—11 के उपबन्ध—अ के तहत वाद हेतुक के प्रकटीकरण (Cause of action) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:—

> *The court has not to see whether the claim made by the petitioner is likely to succeed: it has merely to satisfy itself that the allegations made in the petition, if accepted as true, would entitle the petitioner to the relief he claims. If accepting those allegations as true no case is made out for granting relief no cause of action would be shown and the petition must be rejected. But in ascertaining whether the petition shows a cause of action the court does not enter upon a trial of the issues affecting the merits of the claim made by the petitioner. It cannot take into consideration the defences which the defendant may raise upon the merits; nor is the court competent to make an elaborate enquiry into doubtful or complicated questions of law or fact. If the allegations in the petition, prima facie, show a cause of action, the court cannot embark upon an enquiry whether the allegations are true in fact, or whether the petitioner will succeed in the claims made by him. By the Statute, the jurisdiction of the Court is restricted to ascertaining whether on the allegations a cause of action is shown: the jurisdiction does not extend to trial of issues which must fairly be left for decision at the hearing of the suit.*

26. माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा उनवान *V. K. John vs W. S. Seetharam* में दिनांक 18.12.2008 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—7 नियम—11 के उपबन्ध—अ के तहत वाद हेतुक के प्रकटीकरण (Cause of action) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:—

> *32. It is trite law which has already been settled in catena of decisions including the above referred citations, an application under Order 7 Rule 11(d) can be filed if the allegations in the*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.24 19:05:53 IST
Reason: SelfAttested

> *plaint appeared to be barred by any law and for this purpose, the averments made in the plaint alone are relevant and the Court would not be entitled to consider the entire defence at this stage. In so far as Order 7 Rule 11(a) of CPC is concerned, when no cause of action is disclosed, the Courts will not unnecessarily protract the hearing of the suit.*

27. माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा उनवान *P .Chidambaram vs R. S. Raja Kannappan* में दिनांक 07.06.2012 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—7 नियम—11 के उपबन्ध—अ के तहत वाद हेतुक के प्रकटीकरण (Cause of action) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार हैः—

> *Normally, a plaint can be rejected only if there is absolutely no cause of action and the same cannot be rejected if there is a lack of cause of action.*

28. माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा उनवान *M. Chinnaiyah vs Naina Mohammed* में दिनांक 30.07.2012 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—7 नियम—11 के उपबन्ध—अ के तहत वाद हेतुक के प्रकटीकरण (Cause of action) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार हैः—

> *The Trial Court can reject a plaint, only when it is found that any of the conditions under Rule 11 of Order 7 of CPC exists. The Trial Court has gone into the merits of the case and rejected the plaint on the ground that the averments stated in the plaint have not been substantiated by documentary evidence, which is clearly a matter of trial. The Trial Court can ascertain as to whether the plaint discloses cause of action or not, but cannot ascertain as to whether the plaintiff would be entitled to get the relief prayed for in the facts and circumstances disclosed in the plaint.*

29. माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा उनवान *Central Government Employees vs Consolidated Civil Construction Ltd* में दिनांक 24.01.2012 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—7 नियम—11 के के उपबन्ध—अ के तहत वाद हेतुक के प्रकटीकरण (Cause of action) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार हैः—

> 149. *In D. Ramachandran v. R.V. Janakiraman64 it has been held that the court cannot dissect the pleading into several parts and consider whether each one of them discloses a cause of action.*
>
> *150. In ascertaining whether the plaint shows a cause of action, the court is not required to make an elaborate enquiry into doubtful or complicated questions of law or fact. By the statute the jurisdiction of the court is restricted to ascertaining whether on the allegations a cause of action is shown. In Vijai Pratap Singh v. Dukh Haran Nath Singh67 this Court held: (AIR pp. 943-44, para 9) By the express terms of Rule 5 clause (d), the court is concerned to ascertain whether the allegations made in the petition show a cause of action. The court has not to see whether the claim made by the petitioner is likely to succeed: it has merely to satisfy itself that the allegations made in the petition, if accepted as true, would entitle the petitioner to the*

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.24 19:05:53 IST
Reason: SelfAttested

relief he claims. If accepting those allegations as true no case is made out for granting relief no cause of action would be shown and the petition must be rejected. But in ascertaining whether the petition shows a cause of action the court does not enter upon a trial of the issues affecting the merits of the claim made by the petitioner. It cannot take into consideration the defences which the defendant may raise upon the merits; nor is the court competent to make an elaborate enquiry into doubtful or complicated questions of law or fact. If the allegations in the petition, prima facie, show a cause of action, the court cannot embark upon an enquiry whether the allegations are true in fact, or whether the petitioner will succeed in the claims made by him.

151. So long as the claim discloses some cause of action or raises some questions fit to be decided by a judge, the mere fact that the case is weak and not likely to succeed is no ground for striking it out. The purported failure of the pleadings to disclose a cause of action is distinct from the absence of full particulars. (See Mohan Rawale63.)

152. The reason for the aforementioned conclusion is that if a legal question is raised by the defendant in the written statement, it does not mean that the same has to be decided only by way of an application under Order 7 Rule 11 of the Code of Civil Procedure which may amount to prejudging the matter.

153. Thus, in terms of law laid down by the Hon'ble Supreme Court, the cause of action is a bundle of facts, which is required to be pleaded and proved for the purposes of obtaining the relief sought for and the Court would be empowered to reject the plaint on the failure of the plaintiff to disclose a cause of action, but the same would not mean that the averments made in the plaint or the document, which have to be relied on, although discloses a cause of action, plaint could be rejected on the ground that it is not sufficient to prove the fact. Further, the Hon'ble Supreme Court also cautioned that the Court cannot dissect the pleadings into several parts and the Court should not embark upon an elaborate enquiry into doubtful or complicated questions of law or facts. Thus the test would be as long as the claim discloses, some cause of action or if it raises some questions, which is fit to be decided, even if the facts of the case reveals that the plaintiff may not succeed, is not a ground to strike down the plaint.

30. माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा उनवान *Urooj Ahmed vs Preethi Kitchen Appliances* में दिनांक 25.09.2013 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—7 नियम—11 के के उपबन्ध—अ के तहत वाद हेतुक के प्रकटीकरण (Cause of action) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार हैः—

5(a)(ii). A cause of action would constitute bundle of facts. It implies a right to sue. There is difference between a non disclosure of cause of action and a defective cause of action. There is no difficulty in appreciating the position of law that an application under Order VII Rule 11 of C.P.C., would govern a case of non disclosure of a cause of action. However, it does not govern a defective cause of action. A question as to whether a plaint discloses a cause of action is a question of fact which has to be governed on the basis of the claims made therein in

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.24 19:05:53 IST
Reason: SelfAttested

entirety. The Court has to take the averments as true and then apply its mind as to whether a plaint discloses a cause of action or not. Applying the abovesaid principles of law, we are of the view that the averments made in the plaint in the case on hand are sufficient enough to disclose a cause of action. The Honourable Apex Court in Kusum Ingots & Alloys Ltd., v. Union of India and another (2004) 6 Supreme Court Cases, 254) has held as follows:

"6.Cause of action implies a right to sue. The material facts which are imperative for the suitor to allege and prove constitutes the cause of action. Cause of action is not defined in any statute. It has, however, been judicially interpreted inter alia to mean that every fact which would be necessary for the plaintiff to prove, if traversed, in order to support his right to the judgment of the Court. Negatively put, it would mean that everything which, if not proved, gives the defendant an immediate right to judgment, would be part of cause of action. Its importance is beyond any doubt. For every action, there has to be a cause of action, if not, the plaint or the writ petition, as the case may be, shall be rejected summarily.

31. माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा उनवान *Instituto Hispania vs Mrs.Vinolia Lobo* में दिनांक 04.08.2009 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के उपबन्ध–अ के तहत वाद हेतुक के प्रकटीकरण (Cause of action) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार हैः–

151. In ascertaining whether the plaint shows a cause of action, the court is not required to make an elaborate enquiry into doubtful or complicated questions of law or fact. By the statute the jurisdiction of the court is restricted to ascertaining whether on the allegations a cause of action is shown. In Vijai Pratap Singh v. Dukh Haran Nath Singh this Court held: (AIR pp.943-44, para 9). By the express terms of Rule 5 clause (d), the court is concerned to ascertain whether the allegations made in the petition show a cause of action. The court has not to see whether the claim made by the petitioner is likely to succeed: it has merely to satisfy itself that the allegations made in the petition, if accepted as true, would entitle the petitioner to the relief he claims. If accepting those allegations as true no case is made out for granting relief no cause of action would be shown and the petition must be rejected. But in ascertaining whether the petition shows a cause of action the court does not enter upon a trial of the issues affecting the merits of the claim made by the petitioner. It cannot take into consideration the defences which the defendant may raise upon the merits; nor is the court competent to make an elaborate enquiry into doubtful or complicated questions of law or fact. If the allegations in the petition, prima facie, show a cause of action, the court cannot embark upon an enquiry whether the allegations are true in fact, or whether the petitioner will succeed in the claims made by him.

152. *So long as the claim discloses some cause of action or raises some questions fit to be decided by a judge, the mere fact that the case is weak and not likely to succeed is no ground for striking it out. The purported failure of the pleadings to disclose a cause of action is distinct from the absence of full particulars.*

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.24 19:05:53 IST
Reason: SelfAttested

32. सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—7 नियम—11 के उपबन्ध—ए के तहत दावा के वादहेतुक नहीं होने के बिन्दु पर उपरोक्त न्यायिक दृष्टातों के अवलोकन से यह सिद्धांत प्रतिपादित किये गये हैं कि वाद पत्र में वादी द्वारा किये गये अभिवचनों की सारगर्भित पठन के पश्चात् वाद पत्र में दावा लाने के अधिकार के तहत स्पष्ट वादहेतुक उत्पन्न होना चाहिए। अगर वादी द्वारा वाद पत्र में वादी द्वारा किये गये अभिवचनों की सारगर्भित पठन के पश्चात् वाद पत्र में दावा लाने के अधिकार के तहत स्पष्ट वादहेतुक उत्पन्न नहीं होकर आभासी वादहेतुक उत्पन्न करने हेतु वाद पत्र के अभिवचनों को बारीकी से संरचित किया जाना प्रतीत हो तो वाद को स्पष्ट वादहेतुक पर आधारित नहीं माना जा सकता है।

33. प्रकरण में वादपत्र के अभिवचनों के सारतः अवलोकन से ज्ञात होता है कि वादी द्वारा अपने वादपत्र के अभिवचनों में स्वीकार किया है कि वादी द्वारा दिनांक 25.01.2017 को जरिये पंजीबद्ध हकतर्कनामा अपने हक का सुजाराम के पक्ष में हकतर्क कर दिया गया है। इससे प्रतीत होता है कि जब वादी द्वारा स्वयं दिनांक 25.01.2017 को जरिये पंजीबद्ध हकतर्कनामा अपने हक का सुजाराम के पक्ष में हकतर्क कर दिया गया है। तो उक्त वादहेतुक पर वादी को दावा लाने का अधिकार समाप्त हो जाता है। अर्थात्त उक्त वाद को लाने का वादहेतुक उत्पन्न नहीं होता है। इस आधार पर वादी को उक्त खातेदारी आराजी के संबंध में दावा लाने का आधार एवं वादहेतुक उत्पन्न होना स्पष्ट नहीं होता है। इस प्रकार प्रकरण में वादी को दावा लाने का अधिकार नहीं होने व वादी को दावा लाने हेतु कोई वादहेतुक उत्पन्न नहीं होने के आधार पर दावा सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—7 नियम—11 के तहत प्रकरण वादहेतुक उत्पन्न नहीं होने की श्रेणी के अन्तर्गत प्रतीत होता है। उक्त दावा सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—7 नियम—11 के तहत खारिज किये जाने की श्रेणी के अन्तर्गत प्रतीत होने के आधार पर खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

34. इसके साथ ही प्रकरण में सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—7 नियम—11 के उपबन्ध—डी के तहत वाद को रेस—ज्यूडिकेटा से संबंधित विधि द्वारा वर्जित बताया गया है। इस संबंध में (Barred by Law) के संबंध में न्यायिक दृष्टान्तों उद्धरण यहां प्रासंगिक है।

<u>Barred by Law</u>

35. सर्वप्रथम माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा उनवान *M.Nelson Babu vs K.Kamalesh Babu* में दिनांक 15.09.2009 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—7 नियम—11 आदेश—7 नियम—11 के उपबन्ध—डी के तहत विधि द्वारा वर्जित (Barred by Law) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार हैः—

> *11. <u>Order 7 Rule 11(d) has limited application</u>. For its applicability, it must be shown that the present suit is barred under law. Such a conclusion must be drawn from the averments made in the plaint. What would be the relevant for invoking Order 7 Rule 11(d) of CPC are the averments made in the plaint and for that purpose, there cannot be any addition or subtraction. For the purpose of invoking the said provision, no amount of evidence can be looked into.*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.24 19:05:53 IST
Reason: SelfAttested

36. माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा उनवान *Dega Jayalakshmi & Others Vs. Kapoor Enterprises* में दिनांक 26.08.2009 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—7 नियम—11 के उपबन्ध—डी के तहत विधि द्वारा वर्जित (Barred by Law) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार हैः—

> *The language of Order VII Rule 11 CPC is quite clear and unambiguous. The plaint can be rejected on the ground of limitation only where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law. Law within the meaning of clause (d) of Order VII Rule 11 must include the law of limitation as well.*

37. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 3460/2000 उनवान *Popat and Kotecha Property Vs. State Bank of India Staff Association* में दिनांक 29.08.2005 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—7 नियम—11 के उपबन्ध—डी के तहत विधि द्वारा वर्जित (Barred by Law) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार हैः—

> *Clause (d) of Order VII Rule 7 speaks of suit, as appears from the statement in the plaint to be barred by any law. Disputed questions cannot be decided at the time of considering an application filed under Order VII Rule 11 CPC. Clause (d) of Rule 11 of Order VII applies in those cases only where the statement made by the plaintiff in the plaint, without any doubt or dispute shows that the suit is barred by any law in force.*

38. माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा उनवान *Balachandra Builders Vs. Anis and others* में दिनांक 01.03.2017 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—7 नियम—11 के उपबन्ध—डी के तहत विधि द्वारा वर्जित (Barred by Law) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार हैः—

> *24. Yet another contention of the learned counsel for the applicant/original 6th defendant is that the suit has to be rejected on the ground of limitation. According to the learned counsel though plea of limitation is generally mixed question of law and facts, when the suit itself is filed beyond the period of limitation, as specifically provided, the suit should be rejected under Order 7 Rule 11 (d), 7 and 8 CPC. In support of his contention, the learned counsel relied on the judgment reported in wherein the Hon'ble Apex Court in paragraph No.25 and 41 held as follows:*
>
> *"25.The language of Order 7, Rule 11, C.P.C. is quite clear and unambiguous. The plaint can be rejected on the ground of limitation only where the Suit appears from the statement in the Plaint to be barred by any law. Mr.Nariman did not dispute that "law" within the meaning of clause (d) of Order 7, Rule 11 must include the law of limitation as well. It is well settled what whether a Plaint discloses a cause of action is essentially a question of fact, but whether it does or does not must be found out from reading the Plaint itself. For the said purpose the averments made in the plaint in their entirety must be held to be correct. The test is whether the averments made in the Plaint, if taken to be correct in their entirety a decree would be passed.*

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.24 19:05:53 IST
Reason: SelfAttested

> *The averments made in the Plaint as a whole have to be seen to find out whether clause (d) of Rule 11 of Order 7 is applicable. It is not permissible to cull out a sentence or a passage and to read it out of the context in isolation. Although it is the substance and not merely the form that has to be looked into, the pleading has to be construed as it stands without addition or subtraction of words or change of its apparent grammatical sense. As observed earlier, the language of clause (d) is quite clear but if any authority is required, one may usefully refer to the judgments of this court in Liverpool & London S.P. & I Assn. Ltd. v. M.V. Sea Success I and Popat and Kotecha Property v. state Bank of India Staff Assn.*

39. माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा उनवान *Kasthuri and others Vs. Baskaran and another* में दिनांक 22.08.2003 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—7 नियम—11 के के उपबन्ध—डी के तहत विधि द्वारा वर्जित (Barred by Law) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार हैः—

> *19. It is settled law as held by various Courts that where on the face of the plaint, a suit appears to be barred by any law, the Court shall dismiss the suit. But where it does not so appear, but requires further consideration or, in other words, if there be any doubt or if the Court is not sure and certain that the suit is barred by some law, the Court cannot reject the plaint under Clause (d) of Order 7 Rule 11 of C.P.C.*
> *20. In this context, it would be relevant to quote the observation made by the Bombay High Court in A.I.R.1999 Bombay 161 (supra), with which I entirely agree. The observation is as follows:*
>
> *"It is settled law that the plaint can be rejected as disclosing no cause of action if the Court finds that it is plain and obvious that the case put forward is unarguable. The phrase "does not disclose a cause of action" has to be very narrowly co ued. Rejection of the plaint at the threshold entails very serious consequences for the plaintiff. This power has, therefore, to be used in exceptional circumstances. The Court has to be absolutely sure that on a meaningful reading of the plaint it does not make out any case. The plaint can only be rejected where it does not disclose a cause of action or where the suit appears from the statements made in the plaint to be barred by any provision of the law. While exercising the power of rejecting the plaint, the Court has to act with utmost caution. This power ought to be used only when the Court is absolutely sure that the plaintiff does not have an arguable case at all. The exercise of this power though arising in civil procedure, can be said to belong to the realm of criminal jurisprudence and any benefit of the doubt must go to the plaintiff, whose plaint is to be branded as an abuse of the process of the Court. This jurisdiction ought to be very sparingly exercised and only in very exceptional cases. The exercise of this power would not be justified merely because the story told in the pleadings was highly improbable or which may be difficult to believe."*

40. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 4766 / 2001 उनवान *Ramesh B. Desai and Others Vs. Bipin Vadilal Mehta and Others,* में दिनांक 11.07.2006 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.24 19:05:53 IST
Reason: SelfAttested

दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—7 नियम—11 के उपबन्ध—डी के तहत विधि द्वारा वर्जित (Barred by Law) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार हैः—

> *The plaint without addition or subtraction must show that it is barred by any law to attract application of Order 7 Rule 11 CPC. The principle is, therefore, well settled that in order to examine whether the plaint is barred by any law, as contemplated by sub-rule (d) of Order VII Rule 11 CPC, the averments made in the plaint alone have to be seen and they have to be assumed to be correct. It is not permissible to look into the pleas raised in the written statement or to any piece of evidence.*

41. माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा उनवान *Chandra Vs. Reddappa Reddy* में दिनांक 10.06.2011 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—7 नियम—11 के उपबन्ध—डी के तहत विधि द्वारा वर्जित (Barred by Law) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार हैः—

> *When a part of the relief sought for in the plaint is within time and even if another part of the relief sought for in the plaint is barred by limitation, a plaint cannot be rejection in part. A plaint cannot be rejected in part is a well settled proposition of law. Therefore, the trial court is right in rejecting the application. Further, it has to be pointed out that it is also well settled that the question of limitation is a mixed question of law and fact and therefore that has to be decided only on the basis of the evidence adduced in the trial and therefore the trial court is right in rejecting the application.*

42. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 2517 / 2007 उनवान *Hardesh Ores Pvt. Ltd vs M/S. Hede And Company* में दिनांक 15.05.2007 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—7 नियम—11 के उपबन्ध—डी के तहत विधि द्वारा वर्जित (Barred by Law) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार हैः—

> *21. The language of Order VII Rule 11 CPC is quite clear and unambiguous. The plaint can be rejected on the ground of limitation only where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law. Mr. Nariman did not dispute that "law" within the meaning of clause (d) of Order VII Rule 11 must include the law of limitation as well. It is well settled that whether a plaint discloses a cause of action is essentially a question of fact, but whether it does or does not must be found out from reading the plaint itself. For the said purpose the averments made in the plaint in their entirety must be held to be correct. The test is whether the averments made in the plaint if taken to be correct in their entirety a decree would be passed. The averments made in the plaint as a whole have to be seen to find out whether clause (d) of Rule 11 of Order VII is applicable. It is not permissible to cull out a sentence or a passage and to read it out of the context in isolation. Although it is the substance and not merely the form that has to be looked into, the pleading has to be construed as it stands without addition or subtraction of words or change of its apparent grammatical sense. As observed earlier, the language of clause*

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.24 19:05:53 IST
Reason: SelfAttested

(d) is quite clear but if any authority is required, one may usefully refer to the judgments of this court in Liverpool & London S.P. & I Association Ltd. Vs. M.V. Sea Success I and another : (2004) 9 SCC 512 and Popat and Kotecha Property Vs. State Bank of India Staff Association : (2005) 7 SCC 510.

43. प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा अभिकथन किया गया है कि रिड़मलराम वर्तमान में स्वयं जीवित है। जबकि हस्तगत दावा उनके पुत्र हरीराम द्वारा वादमित्र बनकर प्रस्तुत किया है। इस प्रकार बिना सक्षम न्यायालय से स्वयं को वादमित्र घोषित किये तथा सक्षम चिकित्सक द्वारा बिना चिकित्सकीय परीक्षण किये रिड़मलराम को विकृत चित, निर्योग्य व्यक्ति घोषित किये तथा रिड़मलराम को बिना बताए अपने आप ही वादमित्र बनकर गलत प्रक्रिया के अनुसार दावा प्रस्तुत किया है। अतः हस्तगत दावा बिना वादहेतुक के प्रस्तुत होने तथा विधि वर्जित है। साथ ही वादी द्वारा अभिकथन किया गया है कि वादी द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–32 नियम–15 के तहत वादमित्र नियुक्त किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हुआ है। वादी रिड़मलराम वृद्ध तथा विकृत चित, निर्योग्य व्यक्ति होने के कारण वादमित्र के जरिये ही दावा प्रस्तुत कर सकता है। प्रार्थी / प्रतिवादी का सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र सारहीन होने तथा प्रावधान के अंतर्गत नहीं आता है।

44. प्रकरण में यह निर्विवादित है कि रिड़मलराम स्वयं जीवित है। साथ ही रिड़मलराम को किसी सक्षम चिकित्सक व सक्षम न्यायालय द्वारा निर्योग्य व विकृतचित घोषित नहीं किया जाना भी निर्विवादित है। इस प्रकार रिड़मलराम स्वयं अपना हित की पैरवी करने हेतु कानूनी रूप से सक्षम व्यक्ति है। प्रकरण में स्वयं रिड़मलराम के द्वारा दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है। बल्कि पुत्र हरीराम के द्वारा वादमित्र बनकर रिड़मलराम की तरफ से दावा प्रस्तुत किया गया है। इससे प्रतीत होता है कि प्रकरण में रिड़मलराम को किसी सक्षम चिकित्सक व सक्षम न्यायालय द्वारा निर्योग्य व विकृतचित घोषित किया जाकर हरीराम को किसी सक्षम न्यायालय द्वारा वादमित्र घोषित नहीं किया गया है। इस आधार पर वादी को रिड़मलराम के स्थान पर दावा प्रस्तुत करने का आधार या वादहेतुक उत्पन्न नहीं होता है। साथ ही इस प्रकार वादी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत दावा सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के तहत विधि द्वारा वर्जित प्रतीत होता है।

45. इस प्रकार उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तो के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण का निर्णयन गुणावगुण के आधार पर किया जाना अपेक्षित नहीं है। प्रकरण में उक्त आधार पर दावा सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के तहत प्रकरण विधि द्वारा वर्जित की श्रेणी के अन्तर्गत प्रतीत होता है। साथ ही प्रकरण में वादी को दावा लाने का अधिकार नहीं होने व वादी को दावा लाने हेतु कोई वादहेतुक उत्पन्न नहीं होने के आधार पर दावा सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के तहत प्रकरण वादहेतुक उत्पन्न नहीं होने की श्रेणी के अन्तर्गत प्रतीत होता है। अतः सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के तहत खारिज किये जाने की श्रेणी के अन्तर्गत प्रतीत होने के आधार पर वादपत्र खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.24 19:05:53 IST
Reason: SelfAttested

सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—7 नियम—11 के तहत अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दावा खारिज किया जाता है।

उक्त निर्णय आज 22.12.2025 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढ़ामालानी—बाड़मेर

सहायक कलक्टर/उपखंड अधिकारी गुढ़ामालानी
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.24 19:05:53 IST
Reason: SelfAttested